शुक्रवार, 19 जून 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

महिला टी20 विश्व कप में भारत की लगातार दूसरी जीत

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

'बटवारा 1947' के टीजर ने जगाई 'गदर' की याद

Page-05

फाइनेंशियल इन्क्लूजन से स्पेस टेक तक, भारत बढ़ा रहा मानव क्षमता का दायरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत फाइनेंशियल इन्क्लूजन, शिक्षा, टेलीमेडिसिन, खेती और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है और इसके स्टार्टअप कई नई पार्टनरशिप कर रहे हैं। VivaTech 2026 में बोलते हुए, PM मोदी ने कहा कि भारत स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर न्यूक्लियर एनर्जी तक इंसानी क्षमता के दायरे को बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे VivaTech के 10वें एडिशन के लिए पेरिस में आकर खुशी हो रही है। यह यूरोप का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट है। मैं VivaTech की सफलता के लिए प्रेसिडेंट मैक्रों और आयोजकों को बधाई देता हूं। 2026 भारत और यूरोप के लिए एक खास साल है। साल की शुरुआत में, हमने ऐतिहासिक भारत-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरा किया। यह एग्रीमेंट हमारे व्यापार और निवेश को बढ़ाएगा। और यह टैलेंट, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म के आदान-प्रदान के लिए कई रास्ते खोलेगा। उन्होंने कहा कि इस साल 'भारत-फ्रांस इनोवेशन ईयर' की शुरुआत के साथ, फ्रांस एक अहम कड़ी का काम कर रहा है जो भारत और यूरोप के टेक इकोसिस्टम को करीब ला रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का मानना है कि बदलाव के इस दौर में टेक्नोलॉजी का फ़ायदा सभी को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम फाइनेंशियल इन्क्लूजन, शिक्षा, टेलीमेडिसिन, खेती और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ दिन पहले नीस में हुए 'भारत इनोवेट्स' से लेकर आज पेरिस में हो रहे 'विवा टेक' तक, हमारे स्टार्टअप कई नई साझेदारियां कर रहे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर न्यूक्लियर एनर्जी तक, हम इंसानी क्षमता का दायरा बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में भारत तेज़ी से बदल रहा है और इस बदलाव की वजह टेक्नोलॉजी है। उन्होंने कहा कि फ्रांस में भी एफिल टॉवर या पेरिस एयरपोर्ट पर UPI का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम बनाने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाने तक... फाइनेंशियल इन्क्लूजन, शिक्षा, टेलीमेडिसिन, खेती और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। हमारे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की वजह से आज दुनिया के आधे रियल-टाइम डिजिटल ट्रांज़ैक्शन भारत में होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब आप फ्रांस में भी एफिल टॉवर या पेरिस एयरपोर्ट पर UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी कई वर्ल्ड-क्लास डिजिटल पब्लिक गुड्स (जन-सुविधाएं) के उदाहरण हैं। डिजिलॉकर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट में से एक है।

पेरिस के VivaTech 2026 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत तकनीक के जरिए वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में बदलाव ला रहा है। UPI, डिजिलॉकर और भारत-EU साझेदारी इसकी बड़ी मिसाल हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री गुजराल के बेटे से ₹7.80 करोड़ की साइबर ठगी

देश में बढ़ते साइबर अपराधों के बीच एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के पुत्र और पूर्व राज्यसभा सांसद नरेश कुमार गुजराल कथित तौर पर ₹7.80 करोड़ की साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार साइबर अपराधियों ने व्हाट्सएप पर नरेश गुजराल की तस्वीर और पहचान का दुरुपयोग कर उनके स्टाफ को धोखे में लिया और कई चरणों में बड़ी धनराशि ट्रांसफर करवा ली।पुलिस सूत्रों के अनुसार अपराधियों ने बेहद योजनाबद्ध तरीके से इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया। उन्होंने व्हाट्सएप पर ऐसा अकाउंट बनाया जो देखने में पूरी तरह नरेश गुजराल का प्रतीत होता था। इसके बाद स्टाफ से तत्काल वित्तीय जरूरत का हवाला देकर अलग-अलग खातों में धनराशि भेजने को कहा गया। चूंकि संदेश परिचित व्यक्ति के नाम और तस्वीर के साथ आया था, इसलिए कर्मचारियों को शुरुआत में किसी धोखाधड़ी का संदेह नहीं हुआ। मामले का खुलासा तब हुआ जब धनराशि के लेन-देन की पुष्टि के दौरान असामान्य गतिविधियों का पता चला। शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की साइबर सेल सक्रिय हुई और जांच शुरू कर दी गई। अधिकारियों ने बताया कि अब तक लगभग ₹4 करोड़ की राशि विभिन्न बैंक खातों में फ्रीज कर दी गई है और शेष धनराशि की ट्रैकिंग जारी है।

प्रधानमंत्री मोदी की बिजनेस डिप्लोमेसी सेंट-गोबेन CEO से महत्वपूर्ण मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में वैश्विक निर्माण सामग्री कंपनी सेंट-गोबेन के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बेनोइट बाज़िन से महत्वपूर्ण मुलाकात की। यह बैठक प्रधानमंत्री की तीन देशों की यात्रा के दौरान हुई और इसे भारत-फ्रांस आर्थिक संबंधों को नई मजबूती देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद पेरिस पहुंचे, जहां उन्होंने कई प्रमुख उद्योगपतियों और नीति निर्माताओं से मुलाकात की।बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत में निवेश, विनिर्माण, हरित प्रौद्योगिकी, टिकाऊ निर्माण और औद्योगिक सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा की। सेंट-गोबेन पहले से ही भारत में बड़े स्तर पर निवेश कर चुकी है और देश के निर्माण तथा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में उसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति है। माना जा रहा है कि इस बातचीत में भारत में भविष्य के निवेश अवसरों और नई परियोजनाओं पर भी विचार-विमर्श हुआ।प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का एक प्रमुख आकर्षण VivaTech 2026 सम्मेलन भी है, जिसे यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप आयोजन माना जाता है। इस वर्ष भारत को "AI पार्टनर देश" का विशेष दर्जा मिला है। इससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल नवाचार और स्टार्टअप सहयोग के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को मान्यता मिली है। सम्मेलन में दुनिया भर के उद्योगपति, निवेशक, तकनीकी विशेषज्ञ और नीति निर्माता भाग ले रहे हैं।

PM किसान की 23वीं किस्त कल होगी जारी, किसानों के खातों में आएंगे ₹2,000

पीएम किसान की 23वीं किस्त का इंतज़ार खत्म हो गया है। 2,000 रुपये की अगली किस्त 20 जून, 2026 को किसानों के खातों में जारी की जाएगी। PM किसान सम्मान निधि के आधिकारिक X हैंडल ने लिखा कि PM-KISAN योजना की 23वीं किस्त 20 जून, 2026 को जारी की जाएगी, जिससे किसानों के बैंक खातों में सीधे समय पर आर्थिक मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च को असम के गुवाहाटी में PM किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी की और 9.32 करोड़ किसानों को 18,640 करोड़ रुपये बांटे। इन 22 किस्तों के ज़रिए, PM मोदी ने इस योजना के तहत 4.25 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि बांटी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 20 जून को दोपहर 3:45 बजे, 'पीएम किसान उत्सव दिवस' पर, पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले के तारकेश्वर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। अब तक, 22 किस्तों के ज़रिए लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खातों में करीब 4 लाख 28 हज़ार करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं, और 20 तारीख को इस फंड के ज़रिए देश भर के किसानों के खातों में 18,800 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा ठीक से नहीं मिल पाया है क्योंकि राज्य सरकार ने लाभार्थियों की सूची ठीक से नहीं भेजी है। अब, 44 लाख से ज़्यादा किसानों के खातों में 885 करोड़ रुपये आएंगे। मध्य प्रदेश में, 23वीं किस्त के तौर पर 21 लाख से ज़्यादा किसानों के खातों में 1634 करोड़ 88 लाख रुपये जमा किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में अब तक 22 किस्तों में किसानों के खातों में 33,721 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं। 'पीएम किसान उत्सव दिवस' का कार्यक्रम देश भर के सभी 731 कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि स्कूलों और राज्य-स्तरीय कार्यक्रमों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री और कृषि मंत्री भी इसमें हिस्सा लेंगे... हर राज्य और ग्राम पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट की अटकलें

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर नए राजनीतिक समीकरणों की चर्चा तेज हो गई है। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के भीतर जल्द बड़ी फूट पड़ने का दावा कर राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कई नेता वर्तमान नेतृत्व से संतुष्ट नहीं हैं और आने वाले समय में पार्टी के भीतर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि संभावित बागी गुट का नेतृत्व पूर्वांचल क्षेत्र का एक प्रभावशाली नेता कर सकता है।राजभर का यह बयान ऐसे समय आया है जब देश के कई राज्यों में विपक्षी दलों के भीतर नेतृत्व और संगठनात्मक मुद्दों को लेकर मतभेदों की खबरें सामने आ रही हैं। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता पार्टी के निर्णयों और संगठनात्मक ढांचे से असहज महसूस कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनके बयान ने राजनीतिक अटकलों को और हवा दे दी है। समाजवादी पार्टी ने राजभर के आरोपों को गंभीरता से लेने से इनकार किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि संगठन पूरी तरह एकजुट है और विपक्षी दलों द्वारा जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। सपा नेताओं ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में संगठन लगातार मजबूत हो रहा है और जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा रहा है।

क्रॉस-वोटिंग की आशंका के बीच NDA समर्थित नथवानी बने राज्यसभा सांसद

झारखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। NDA उम्मीदवार परिमल नथवानी ने झारखंड से राज्यसभा चुनाव जीत लिया है और कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को हार गए है। नतीजों के बाद, कांग्रेस नेताओं ने कुछ विधायकों द्वारा क्रॉस-वोटिंग किए जाने की आशंका जताई है, क्योंकि पार्टी और उसके सहयोगियों से चुनाव में कड़ी टक्कर की उम्मीद थी। वहीं, झामुमो के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम झारखंड से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं। NDA समर्थित राज्यसभा चुनाव उम्मीदवार परिमल नथवानी की जीत पर BJP विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि NDA को 28 वोट मिले, JMM को 30 और कांग्रेस को 19 वोट मिले। 3 वोट रद्द हो गए। परिमल नथवानी को 28 वोट मिले। विधायकों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और ऐसा होना ही था। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि आज झारखंड की जनता और यहां के सम्मानित विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपना लिया है। अगर कोई इस देश और राज्य का भला कर सकता है, तो वह नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी के काम खुद बोलते हैं, उनका काम साफ़ दिखता है। वहीं, कांग्रेस के राज्य प्रभारी के. राजू ने दावा किया कि कांग्रेस के सभी 16 वोट सुरक्षित हैं, JMM ने 4 वोट दिए और कांग्रेस को 20 वोट मिले। यह स्थिति इसलिए बनी क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार ने पैसे का इस्तेमाल किया। राज्यसभा की दो सीट के लिए तीन उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के बैद्यनाथ राम और कांग्रेस के प्रणव झा शामिल हैं। 'क्रॉस वोटिंग' की आशंका के बीच मतदान सुबह नौ बजे शुरू हुआ और अपराह्न लगभग तीन बजे तक चला। मतदान करने वाले 81 विधायकों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी, भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर शामिल हैं।

हिन्दी जगत महामंच

www.tvbharatvarsh.in

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक ई–पेपर

प्रदेश का नं. 1 प्रतिष्ठित हिन्दी न्यूज़ ई–पेपर

विज्ञापन दर

साईज	विजिटिंग कार्ड	क्वाटर पेज	हाफ पेज	फुल पेज (अंदर)	फुल पेज (कवर 2 - 3)	फुल पेज (कवर 4 - अंतिम)	(फ्रंट पेज)
रेट	₹ 3000	₹ 6000	₹ 10,000	₹ 20,000	₹ 25,000	₹ 30,000	₹ 100000

8601780000

अमेरिका-ईरान युद्धविराम समझौते से पश्चिम एशिया में शांति की नई उम्मीद

आंध्र प्रदेश में मेगा DSC शिक्षक भर्ती को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए चंद्रबाबू नायडू सरकार को घेरा है। वहीं राज्य सरकार ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बताया है।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

पश्चिम एशिया में पिछले कई सप्ताह से जारी सैन्य तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्धविराम समझौते ने वैश्विक कूटनीति को नई दिशा दी है। लंबे समय से दोनों देशों के बीच बढ़ते टकराव, समुद्री मार्गों पर खतरे और क्षेत्रीय अस्थिरता को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय चिंतित था। ऐसे समय में दोनों पक्षों द्वारा संघर्ष विराम पर सहमति जताना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। समझौते के तहत तत्काल प्रभाव से सैन्य कार्रवाई रोकने, समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आगे की वार्ताओं के लिए राजनयिक चैनलों को सक्रिय रखने का निर्णय लिया गया है।इस समझौते का सबसे बड़ा प्रभाव ऊर्जा बाजार पर दिखाई दिया। पश्चिम एशिया विश्व के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों में शामिल है और होरमुज जलडमरूमध्य से होकर वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। हाल के तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी गई थी, लेकिन युद्धविराम की घोषणा के बाद बाजारों में राहत का माहौल बना। निवेशकों ने इसे क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में सकारात्मक संकेत माना है।समझौते में परमाणु गतिविधियों की निगरानी को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की भूमिका को मजबूत करने तथा निरीक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने पर सहमति बनी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस दिशा में प्रगति होती है तो भविष्य में परमाणु विवादों को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही क्षेत्रीय देशों के बीच संवाद और विश्वास बहाली के प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा।हालांकि चुनौतियां अभी समाप्त नहीं हुई हैं। दोनों देशों के बीच अविश्वास का लंबा इतिहास रहा है और कई क्षेत्रीय मुद्दों पर मतभेद अब भी कायम हैं। इसलिए इस समझौते की सफलता काफी हद तक इसके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। यदि दोनों पक्ष अपने वादों का पालन करते हैं तो यह पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।विश्व के अनेक देशों ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी इसे सकारात्मक पहल बताया है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि वार्ता का यह क्रम जारी रहता है तो न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में यह समझौता किस प्रकार आगे बढ़ता है और क्या यह पश्चिम एशिया में स्थायी स्थिरता का आधार बन पाता है।

ब्रसेल्स में यूरोपीय परिषद की अहम बैठक शुरू, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर मंथन

यूरोपीय संघ के नेताओं की महत्वपूर्ण परिषद बैठक ब्रसेल्स में शुरू हो गई है, जिसमें महाद्वीप की सुरक्षा, आर्थिक विकास, ऊर्जा आपूर्ति और प्रवासन जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक को यूरोपीय संघ की भविष्य की नीतियों और रणनीतियों के निर्धारण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक ऐसे समय में हो रही है जब यूरोप एक साथ कई चुनौतियों का सामना कर रहा है।बैठक का प्रमुख विषय रूस-यूक्रेन युद्ध और उससे उत्पन्न सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं। यूरोपीय नेता यूक्रेन को दी जा रही सहायता की समीक्षा कर रहे हैं और भविष्य में सहयोग के नए उपायों पर चर्चा कर रहे हैं। कई देशों का मानना है कि यूक्रेन को समर्थन जारी रखना यूरोप की सामूहिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही युद्ध के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजारों पर भी चर्चा हो रही है।ऊर्जा सुरक्षा इस बैठक का एक अन्य प्रमुख मुद्दा है। पश्चिम एशिया में हालिया तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता को देखते हुए यूरोपीय देश वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और दीर्घकालिक आपूर्ति योजनाओं पर विचार कर रहे हैं। ऊर्जा कीमतों को नियंत्रित रखने और उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बनाए रखने के लिए कई प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है।प्रवासन और सीमा सुरक्षा भी परिषद की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। यूरोप के कई देशों में अवैध प्रवासन और शरणार्थी संकट को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। सदस्य देश ऐसी नीतियों पर सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो मानवीय मूल्यों और सुरक्षा आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित कर सकें।इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ के आगामी दीर्घकालिक बजट, तकनीकी प्रतिस्पर्धा, हरित ऊर्जा संक्रमण और वैश्विक व्यापार संबंधों पर भी विचार किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बैठक में लिए जाने वाले निर्णय आने वाले वर्षों में यूरोप की आर्थिक और सामरिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

भाजपा से निष्कासित दोनों विधायक ने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दिया

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

कर्नाटक में विधान परिषद की सात सीटों पर आज मतदान हो रहा है और इन सीटों पर आठ प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस चुनाव में भाजपा के साथ खेला हो गया है और उसके दो विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दिया है। भाजपा से निष्कासित दोनों विधायक, ST सोमशेखर और शिवराम हेब्बार ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया है। दोनों विधायक मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ तस्वीर में नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि भाजपा के इन विधायकों की क्रॉस-वोटिंग से कांग्रेस को काउंसिल में पांचवीं सीट हासिल करने के लिए जरूरी संख्या जुटाने में मदद मिलेगी। बता दें कि कर्नाटक में कुछ दिनों पहले सत्ता परिवर्तन हुआ है और डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बने हैं। सीएम पद का कार्यभार संभालने के बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए यह पहली चुनावी लड़ाई है। कर्नाटक के विधान सौध में मतदान जारी है। मतदान के बीच भाजपा के दो विधायकों का सीएम के साथ गलबहियां करना कुछ अलग संदेश दे रहा है। निर्वाचन अधिकारी के अनुसार मतदान सुबह नौ बजे शुरू हुआ और आज शाम चार बजे तक चलेगा, जबकि मतगणना शाम पांच बजे शुरू होगी और आज ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि जीत के लिए हर उम्मीदवार को कम से कम 28 वोट की जरूरत है। अधिकारियों ने बताया कि विधानसभा में अपनी संख्या बल पर कांग्रेस और भाजपा छह में से चार और दो सीट आसानी से जीत सकती हैं। लेकिन सातवीं सीट के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस और जनता दल (सेक्यूलर) दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और दोनों पार्टियों में से किसी के पास इस सीट को जीतने की ताकत नहीं है। ऐसे में सत्तारूढ़ कांग्रेस निर्दलीय और भाजपा से निष्कासित विधायकों की मदद से सात में से पांच सीटें जीतने की जुगाड़ में है।

नाटो सहयोगियों पर अमेरिका का दबाव बढ़ा रक्षा खर्च में वृद्धि की मांग

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

ब्रसेल्स में आयोजित नाटो रक्षा मंत्रियों की बैठक में अमेरिका ने एक बार फिर सदस्य देशों से रक्षा खर्च बढ़ाने की जोरदार मांग की है। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच यूरोपीय देशों को अपनी सुरक्षा जिम्मेदारियों में अधिक योगदान देना चाहिए। बैठक के दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि नाटो की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था तभी प्रभावी रह सकती है जब सभी सदस्य देश समान रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें।अमेरिका लंबे समय से यह मुद्दा उठाता रहा है कि कई नाटो सदस्य देश संगठन द्वारा निर्धारित रक्षा व्यय लक्ष्य को पूरा नहीं कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में रूस-यूक्रेन युद्ध, साइबर सुरक्षा चुनौतियों और वैश्विक सामरिक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए रक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ाना आवश्यक हो गया है। अमेरिकी पक्ष का तर्क है कि यूरोप की सुरक्षा केवल अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं हो सकती और सहयोगी देशों को भी अपनी सैन्य क्षमता मजबूत करनी होगी।बैठक में यूरोप में तैनात अमेरिकी सैनिकों की भूमिका और भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा हुई। कुछ रिपोर्टों में संकेत दिए गए हैं कि अमेरिका अपनी वैश्विक सैन्य प्राथमिकताओं की समीक्षा कर रहा है और संसाधनों के अधिक संतुलित उपयोग पर विचार कर सकता है। इस कारण यूरोपीय देशों के सामने अपनी रक्षा तैयारियों को और मजबूत बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।नाटो के कई सदस्य देशों ने हाल के वर्षों में रक्षा बजट में वृद्धि की है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अभी भी कई देशों को निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। यूरोप में सुरक्षा चुनौतियों के बढ़ते दायरे को देखते हुए सामूहिक रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना समय की आवश्यकता माना जा रहा है।विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों के बीच यह बहस केवल बजट तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की सुरक्षा रणनीति और जिम्मेदारियों के बंटवारे से भी जुड़ी हुई है। आने वाले वर्षों में नाटो की दिशा और संरचना पर इन चर्चाओं का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

जी-7 देशों ने यूक्रेन को अतिरिक्त सैन्य और आर्थिक सहायता देने का किया ऐलान

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

फ्रांस में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने यूक्रेन को निरंतर समर्थन देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सम्मेलन के दौरान नेताओं ने रूस-यूक्रेन युद्ध की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत चर्चा की और यह स्पष्ट किया कि यूक्रेन को सैन्य, आर्थिक तथा मानवीय सहायता जारी रखी जाएगी। संयुक्त बयान में कहा गया कि यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्राथमिकताओं में शामिल है।बैठक में यूक्रेन की वायु रक्षा क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। सदस्य देशों ने मिसाइल रक्षा प्रणालियों, सैन्य उपकरणों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विस्तार पर सहमति व्यक्त की। इसके अलावा युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता बढ़ाने की योजना पर भी विचार किया गया। नेताओं का मानना है कि केवल सैन्य सहयोग ही नहीं बल्कि आर्थिक स्थिरता भी यूक्रेन के भविष्य के लिए आवश्यक है।यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने सम्मेलन के दौरान कई प्रमुख नेताओं से मुलाकात की और युद्ध की ताजा स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने सहयोगी देशों से समर्थन बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि रूस के लगातार हमलों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहायता अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी-7 देशों ने यह भी संकेत दिया कि यदि आवश्यक हुआ तो रूस पर अतिरिक्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।विशेषज्ञों के अनुसार यह निर्णय दर्शाता है कि पश्चिमी देश अभी भी यूक्रेन के समर्थन के मुद्दे पर एकजुट हैं। हालांकि युद्ध के लंबे खिंचने से आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां भी बढ़ी हैं, फिर भी जी-7 देशों का रुख स्पष्ट है कि वे यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आने वाले महीनों में इस सहायता का प्रभाव युद्ध की दिशा और कूटनीतिक प्रयासों दोनों पर पड़ सकता है।

संपादक की कलम से

युवाओं की आवाज और शिक्षा व्यवस्था की चुनौती: राजस्थान के कोटा से शुरू हुआ 'छात्रों की गूंज' अभियान एक बार फिर देश की शिक्षा व्यवस्था, भर्ती प्रक्रियाओं और युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ले आया है। चाहे इस अभियान को राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए या सामाजिक पहल के रूप में, यह तथ्य निर्विवाद है कि देश का युवा वर्ग आज कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी, सीमित रोजगार अवसर और बढ़ता मानसिक दबाव लाखों विद्यार्थियों के लिए चिंता का विषय बन चुके हैं।भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में शामिल है। यह स्थिति देश के लिए एक बड़ी शक्ति भी हो सकती है और चुनौती भी। यदि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, निष्पक्ष अवसर और रोजगार उपलब्ध कराए जाएं तो वे राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। लेकिन यदि उनकी आकांक्षाओं और मेहनत को उचित मंच नहीं मिलता, तो निराशा और असंतोष का माहौल पैदा होना स्वाभाविक है।पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों और राष्ट्रीय स्तर की कई परीक्षाओं में पेपर लीक तथा अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। इन घटनाओं ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाए हैं। एक छात्र वर्षों तक कठिन परिश्रम करता है, परिवार अपनी आर्थिक क्षमता से अधिक खर्च करता है, लेकिन जब परीक्षा की निष्पक्षता ही संदिग्ध हो जाए तो युवाओं का भरोसा डगमगाना स्वाभाविक है। यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि लाखों सपनों पर सीधा आघात है।इसके साथ ही समाज में सफलता की परिभाषा को लेकर भी गंभीर पुनर्विचार की आवश्यकता है। आज भी डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सेवक या कुछ चुनिंदा पेशों को ही सफलता का पर्याय मान लिया जाता है। इससे बड़ी संख्या में युवा अनावश्यक दबाव में आ जाते हैं। नई अर्थव्यवस्था के दौर में कौशल आधारित रोजगार, उद्यमिता, नवाचार, खेल, कला और रचनात्मक क्षेत्रों में भी अपार संभावनाएं मौजूद हैं। शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करवाना नहीं, बल्कि व्यक्तित्व और प्रतिभा का समग्र विकास होना चाहिए।हालांकि इस विषय पर राजनीति भी होती रही है। विपक्ष सरकार को घेरता है और सरकार सुधारों का दावा करती है। लेकिन युवाओं के भविष्य जैसे संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रखा जा सकता। आवश्यकता इस बात की है कि सभी राजनीतिक दल, शिक्षा विशेषज्ञ और नीति निर्माता मिलकर ऐसी व्यवस्था विकसित करें जिसमें परीक्षाएं पूरी तरह सुरक्षित हों, भर्ती प्रक्रियाएं समयबद्ध हों और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हों।देश का भविष्य उसके युवाओं के हाथों में है। इसलिए उनकी समस्याओं को सुनना, समझना और उनका समाधान करना केवल राजनीतिक दायित्व नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आवश्यकता है। यदि शिक्षा और रोजगार व्यवस्था में पारदर्शिता, गुणवत्ता और विश्वास स्थापित किया जा सके, तो भारत की युवा शक्ति वास्तव में देश की सबसे बड़ी पूंजी सिद्ध होगी।

राहुल गांधी ने कोटा से शुरू किया छात्र आंदोलन

शिक्षा व्यवस्था को बताया 'एक्सटॉर्शन मशीन'

देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर छात्रों और युवाओं में लंबे समय से असंतोष बना हुआ है। इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने 'छात्रों की गूंज' अभियान शुरू कर शिक्षा व्यवस्था और रोजगार से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाने की रणनीति अपनाई है। कोटा से शुरू हुआ यह अभियान आगामी महीनों में विभिन्न राज्यों तक पहुंचकर छात्रों, अभ्यर्थियों और शिक्षकों के साथ व्यापक संवाद स्थापित करेगा।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा से युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर अपने बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत कर दी। 'छात्रों की गूंज' नामक इस अभियान के जरिए कांग्रेस ने शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और बेरोजगारी को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में लाने का प्रयास शुरू किया है। कोटा में आयोजित विशाल छात्र सम्मेलन में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के बजाय उन्हें असफलता और दबाव की ओर धकेल रही है।राहुल गांधी ने कहा कि देश में लाखों छात्र इंजीनियरिंग, मेडिकल, सिविल सेवा, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में वर्षों का समय और भारी धनराशि खर्च करते हैं, लेकिन पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में देरी उनकी मेहनत पर पानी फेर देती है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को "रिजेक्शन सिस्टम" बताते हुए कहा कि यह युवाओं के सपनों को कुचलने का काम कर रही है। राहुल ने दावा किया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर परिवारों द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि शिक्षा मंत्रालय के वार्षिक बजट से भी अधिक हो चुकी है।कांग्रेस नेता ने छात्रों से पारंपरिक करियर विकल्पों के दबाव से बाहर निकलने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि केवल डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस या कुछ सीमित पेशों को ही सफलता का पैमाना मानना गलत है। शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य युवाओं की रचनात्मकता और क्षमता को विकसित करना होना चाहिए।कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि देशव्यापी अभियान का पहला चरण है। पार्टी के अनुसार कोटा के बाद प्रयागराज, पटना और दिल्ली सहित कई शहरों में छात्र सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। अभियान के दौरान छात्रों, शिक्षकों, प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों और युवा संगठनों से संवाद स्थापित किया जाएगा।राहुल गांधी ने हाल ही में सामने आए पेपर लीक मामलों का उल्लेख करते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मूल समस्या से ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है जबकि आवश्यकता परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की है। दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक करार देते हुए कहा है कि सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। आने वाले दिनों में शिक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख विषयों में शामिल रहने की संभावना है।

विधान परिषद चुनाव से पहले विदर्भ कांग्रेस में गुटबाजी

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में गुरुवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, महासचिवों और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने, राज्यों में राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने और आगामी चुनावों की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई।बैठक ऐसे समय में हुई है जब हाल के चुनावी परिणामों के बाद कांग्रेस संगठन को नए सिरे से सक्रिय करने की कोशिश कर रही है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किए बिना भाजपा के मुकाबले प्रभावी राजनीतिक चुनौती पेश करना कठिन होगा। इसी कारण प्रदेश इकाइयों को अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं।बैठक में युवाओं, किसानों और मध्यम वर्ग से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने पर सहमति बनी। नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय से जुड़े विषयों पर जनसंपर्क अभियान चलाने की रणनीति तैयार की। साथ ही पार्टी के डिजिटल अभियान को भी मजबूत बनाने पर जोर दिया गया।सूत्रों के अनुसार कुछ राज्यों में संगठनात्मक फेरबदल पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस नेतृत्व आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय नेतृत्व को अधिक जिम्मेदारी देने पर विचार कर रहा है। बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर भी चर्चा हुई।राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस आने वाले महीनों में संगठनात्मक पुनर्गठन और जनआंदोलनों के माध्यम से अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने का प्रयास करेगी। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि मजबूत संगठन ही भविष्य की चुनावी सफलता की कुंजी साबित होगा।

महाराष्ट्र में शिवसेना सांसदों के पाला बदलने पर सियासत तेज कांग्रेस ने भाजपा पर लगाए लोकतंत्र कमजोर करने के आरोप

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

महाराष्ट्र की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसदों के पाला बदलने की घटनाओं ने नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के अन्य दलों ने भाजपा पर विपक्षी दलों को कमजोर करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं।महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि यह केवल किसी दल का आंतरिक मामला नहीं है, बल्कि जनता के जनादेश का भी प्रश्न है। उनके अनुसार जिन सांसदों को विपक्षी गठबंधन के समर्थन से जनता ने चुना था, उनका दल बदलना मतदाताओं की भावनाओं के विपरीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता और संसाधनों के प्रभाव का उपयोग कर विपक्षी दलों के जनप्रतिनिधियों को प्रभावित किया जा रहा है।कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार और अन्य विपक्षी नेताओं ने भी इस मुद्दे पर भाजपा को घेरा। उनका कहना है कि लगातार हो रहे दल-बदल से लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लोगों का भरोसा प्रभावित हो सकता है। विपक्षी नेताओं ने इसे विचारधारा और जनादेश दोनों के साथ विश्वासघात बताया है।हालांकि भाजपा ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्ष अपनी आंतरिक कमजोरियों और नेतृत्व संकट को छिपाने के लिए ऐसे आरोप लगा रहा है। पार्टी का दावा है कि जनप्रतिनिधि अपने राजनीतिक भविष्य और क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।स्थानीय निकाय चुनावों से पहले महाराष्ट्र में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों ने राज्य का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले हफ्तों में यह मुद्दा और अधिक तूल पकड़ सकता है तथा महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच राजनीतिक संघर्ष को और तेज कर सकता है।

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारतीय संस्थानों का प्रदर्शन बेहतर आईआईटी दिल्ली देश में शीर्ष पर

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक सकारात्मक खबर सामने आई है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारतीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। इस वर्ष रैंकिंग में भारत के 52 संस्थानों को स्थान मिला है, जिससे भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जिनकी उच्च शिक्षा संस्थानों की वैश्विक उपस्थिति लगातार मजबूत हो रही है। रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बनकर उभरा है, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति में सुधार दर्ज किया है।विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपलब्धि केवल किसी एक संस्थान की सफलता नहीं बल्कि भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में हो रहे व्यापक बदलावों का परिणाम है। पिछले कुछ वर्षों में अनुसंधान, नवाचार, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और उद्योगों के साथ साझेदारी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसका प्रभाव अब वैश्विक रैंकिंग में दिखाई देने लगा है। कई भारतीय संस्थानों ने शोध प्रकाशनों, अकादमिक प्रतिष्ठा और नियोक्ताओं के बीच विश्वसनीयता के मानकों पर बेहतर प्रदर्शन किया है।शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक रैंकिंग केवल प्रतिष्ठा का विषय नहीं होती बल्कि इससे विदेशी विद्यार्थियों को आकर्षित करने, अंतरराष्ट्रीय शोध सहयोग बढ़ाने और वैश्विक निवेश प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है। नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद उच्च शिक्षा संस्थानों को अधिक स्वायत्तता देने, बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देने और शोध गतिविधियों को प्रोत्साहित करने जैसे कदम उठाए गए हैं। इन प्रयासों का लाभ अब धीरे-धीरे दिखाई देने लगा है।हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि अभी भारत के सामने कई चुनौतियां मौजूद हैं। विश्व की शीर्ष दस या शीर्ष पचास विश्वविद्यालयों में भारतीय संस्थानों की संख्या अभी भी सीमित है। अनुसंधान पर निवेश बढ़ाने, शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशालाओं के विकास की दिशा में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।फिर भी इस वर्ष की रैंकिंग भारतीय उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए उत्साहजनक संकेत लेकर आई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय विश्वविद्यालय वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी पहचान मजबूत कर रहे हैं। यदि सुधारों की वर्तमान गति बनी रहती है तो आने वाले वर्षों में भारत की उपस्थिति विश्व की शीर्ष विश्वविद्यालय रैंकिंग में और अधिक प्रभावशाली हो सकती है।

यूजीसी-नेट जून 2026 परीक्षा की तैयारियां अंतिम चरण में, प्रवेश पत्र जारी

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित यूजीसी-नेट जून 2026 परीक्षा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं तथा परीक्षा केंद्रों की जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है। यह परीक्षा देशभर में सहायक प्रोफेसर पद की पात्रता, जूनियर रिसर्च फेलोशिप तथा पीएचडी प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है।यूजीसी-नेट देश की सबसे महत्वपूर्ण उच्च शिक्षा पात्रता परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। हर वर्ष लाखों विद्यार्थी इसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए डिजिटल निगरानी, कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली तथा सुरक्षा संबंधी विशेष प्रबंध किए हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचने और सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।इस वर्ष परीक्षा में विभिन्न विषयों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में बढ़ती रुचि के कारण यूजीसी-नेट की महत्ता लगातार बढ़ रही है। सफल अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापन तथा शोध कार्य के अवसर प्राप्त होते हैं। इसी कारण यह परीक्षा युवाओं के लिए महत्वपूर्ण करियर विकल्प का मार्ग प्रशस्त करती है।शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि देश में गुणवत्तापूर्ण शोध और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऐसी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। परीक्षा के सफल आयोजन से न केवल अभ्यर्थियों का विश्वास मजबूत होगा बल्कि उच्च शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता को भी बल मिलेगा। लाखों छात्र अब परीक्षा और उसके परिणामों का इंतजार कर रहे हैं, जो उनके शैक्षणिक और व्यावसायिक भविष्य की दिशा तय करेंगे।

आईपीएल 2027 का सीजन 10 मार्च से हो सकता है शुरू

महिला टी20 विश्व कप में भारत की लगातार दूसरी जीत, नीदरलैंड को 95 रन से हराया

इंग्लैंड में खेले जा रहे आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए नीदरलैंड को 95 रन के बड़े अंतर से पराजित कर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप चरण में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है तथा सेमीफाइनल की दौड़ में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय टीम ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण तीनों विभागों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एकतरफा मुकाबले में जीत हासिल की।टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। टीम की शुरुआत आक्रामक रही और सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने शानदार 74 रन की पारी खेली। उनके साथ शेफाली वर्मा ने भी तेज अर्धशतक बनाकर टीम को मजबूत आधार प्रदान किया। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी कर नीदरलैंड के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। मध्यक्रम की बल्लेबाजों ने भी तेजी से रन जोड़ते हुए स्कोर को 200 के पार पहुंचाया।209 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड की टीम शुरुआत से ही दबाव में दिखाई दी। भारतीय गेंदबाजों ने सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए नियमित अंतराल पर विकेट हासिल किए। नीदरलैंड की बल्लेबाजी भारतीय आक्रमण के सामने टिक नहीं सकी और पूरी टीम निर्धारित ओवरों में लक्ष्य के करीब भी नहीं पहुंच पाई। भारत की ओर से गेंदबाजों ने सामूहिक प्रदर्शन करते हुए विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का अवसर नहीं दिया।

भारत ने अफगानिस्तान को दूसरे वनडे में 170 रन से हराकर श्रृंखला पर किया कब्जा

भारतीय क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जा रही तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 170 रन की बड़ी जीत दर्ज की और इसके साथ ही श्रृंखला में अजेय बढ़त हासिल कर ली। टीम इंडिया ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में प्रभावशाली खेल दिखाया, जिसके सामने अफगानिस्तान की टीम पूरी तरह संघर्ष करती नजर आई। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने श्रृंखला अपने नाम कर ली और आगामी मैच से पहले ही बढ़त सुनिश्चित कर ली।मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 50 ओवर में मजबूत स्कोर खड़ा किया। शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों ने टीम को सधी हुई शुरुआत दी, जबकि मध्यक्रम ने तेजी से रन बनाकर स्कोर को विशाल रूप दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए और अफगान गेंदबाजों को दबाव में बनाए रखा। टीम की ओर से कई बल्लेबाजों ने उपयोगी योगदान दिया, जिसके कारण अफगानिस्तान के सामने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा हो गया।लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम शुरुआत से ही दबाव में दिखाई दी। भारतीय तेज गेंदबाजों और स्पिनरों ने शानदार तालमेल के साथ गेंदबाजी करते हुए नियमित अंतराल पर विकेट हासिल किए। अफगान बल्लेबाज बड़ी साझेदारी बनाने में असफल रहे और भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का कोई अवसर नहीं दिया। मध्यक्रम के विफल होने के बाद पूरी टीम दबाव में आ गई और निर्धारित लक्ष्य से काफी दूर रह गई। भारतीय कप्तान ने मैच के बाद कहा कि टीम का संतुलित प्रदर्शन जीत का सबसे बड़ा कारण रहा। उन्होंने बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए बड़े स्कोर और गेंदबाजों की अनुशासित गेंदबाजी की सराहना की। टीम प्रबंधन का मानना है कि युवा खिलाड़ियों और अनुभवी क्रिकेटरों के बेहतर संयोजन ने टीम को मजबूती प्रदान की है।

एफआईएच प्रो लीग में भारत ने विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हराया

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एफआईएच प्रो लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से पराजित कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नीदरलैंड्स के रॉटरडैम में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने आक्रामक और संतुलित खेल का प्रदर्शन करते हुए दुनिया की मजबूत टीमों में से एक जर्मनी को मात दी। यह जीत भारत के लिए मनोबल बढ़ाने वाली मानी जा रही है, क्योंकि टीम आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रही है।मुकाबले की शुरुआत से ही भारतीय टीम ने तेज गति से खेल दिखाया। मिडफील्ड और आक्रमण पंक्ति के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिला, जिसके कारण जर्मन रक्षा पंक्ति लगातार दबाव में रही। भारतीय खिलाड़ियों ने मिले अवसरों का लाभ उठाते हुए महत्वपूर्ण गोल किए और बढ़त हासिल कर ली। दूसरी ओर जर्मनी की टीम भारतीय रणनीति का प्रभावी जवाब नहीं दे सकी।इस मुकाबले का एक विशेष पहलू अनुभवी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह की उपलब्धि भी रही। उन्होंने अपने करियर का 413वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेलते हुए भारत के लिए सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। यह उपलब्धि भारतीय हॉकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है।भारतीय टीम के मुख्य कोच ने मैच के बाद खिलाड़ियों की फिटनेस, अनुशासन और सामूहिक प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि विश्व चैंपियन टीम के खिलाफ जीत यह साबित करती है कि भारतीय टीम लगातार प्रगति कर रही है और बड़े मंचों पर चुनौती देने में सक्षम है।हॉकी विशेषज्ञों का मानना है कि इस जीत से भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ेगा और विश्व स्तर पर उसकी स्थिति और मजबूत होगी। प्रो लीग में अच्छे प्रदर्शन का सीधा लाभ भविष्य की प्रमुख प्रतियोगिताओं में टीम को मिल सकता है। भारतीय प्रशंसकों को उम्मीद है कि टीम आने वाले मुकाबलों में भी इसी प्रकार का प्रदर्शन जारी रखेगी।

यमन के 'स्पाइडर-मैन' की मौत, ज्वालामुखी क्रेटर पर चढ़ते समय हादसा

खतरनाक शौक का दर्दनाक अंत

खतरनाक पहाड़ों और ज्वालामुखियों पर बिना किसी सेफ्टी रस्सी के चढ़ने वाले यमन के मशहूर एडवेंचर क्रिएटर अल-काका बिन अंतर की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लाखों लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर 'यमन के स्पाइडर-मैन' के नाम से मशहूर एडवेंचर क्रिएटर अल-काका बिन अंतरअब इस दुनिया में नहीं रहे. 30 साल के कंटेंट क्रिएटर की उस समय मौत हो गई, जब वह बिना किसी सेफ्टी रस्सी के ज्वालामुखी के विशाल क्रेटर पर चढ़ाई कर रहे थे. गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, हादसा यमन के अल धाले प्रांत स्थित हराधत दम्त ज्वालामुखी क्रेटर में हुआ. बताया जा रहा है कि चढ़ाई के दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वह करीब 120 मीटर गहरे क्रेटर में गिर गए. अल-काका बिन अंतर सोशल मीडिया पर अपने खतरनाक एडवेंचर वीडियो के लिए जाने जाते थे. वह अक्सर बिना रस्सी, हार्नेस या किसी सुरक्षा उपकरण के ऊंचे पहाड़ों, चट्टानों और ज्वालामुखियों पर चढ़ते थे.उनके वीडियो को लाखों लोग देखते थे. इसी वजह से उन्हें 'स्पाइडर-मैन ऑफ यमन' का नाम मिला था. स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, हादसे के बाद सिविल डिफेंस की टीमों ने तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया.हालांकि दुर्गम रास्तों, खड़ी चट्टानों और क्रेटर के भीतर मुश्किल हालात के कारण बचाव अभियान आसान नहीं था. करीब 24 घंटे की मशक्कत के बाद टीम ने उनका शव बाहर निकाला. सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन्हें उनके आखिरी पलों का बताया जा रहा है. हालांकि अधिकारियों ने इन वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

एडवेंचर के साथ सुरक्षा भी जरूरी

यह घटना एक बार फिर बताती है कि बिना सुरक्षा उपकरणों के किसी भी जोखिम भरे एडवेंचर में हिस्सा लेना जानलेवा साबित हो सकता है.विशेषज्ञ भी सलाह देते हैं कि पर्वतारोहण, रॉक क्लाइम्बिंग या ज्वालामुखी जैसी जगहों पर हमेशा हेलमेट, हार्नेस और अन्य सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए.

दुबई में 2 साल बाद वापस मिले 18 हजार रूपये

कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी कहानियां सामने आती हैं, जो इंसानियत पर भरोसा और मजबूत कर देती हैं.

दुबई में रहने वाली भारतीय महिला मल्लिका बूबना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. एक छोटी-सी गलती के बाद उन्हें लगा कि मामला वहीं खत्म हो गया, लेकिन दो साल बाद आए एक मैसेज ने उन्हें ही नहीं, बल्कि लाखों लोगों को हैरान कर दिया. यही वजह है कि उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से

वीडियो ने भारत की शहरी व्यवस्था पर उठाए सवाल

शिकागो में तूफान के बाद न थमी रफ्तार, न कटी बिजली

अमेरिका के शिकागो में रहने वाले भारतीय सेना के पूर्व सैनिक यशपाल सिंह मोर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसने सोशल मीडिया पर शहरी व्यवस्थाओं को लेकर नई बहस छेड़ दी है. वीडियो में यशपाल रात करीब 8 बजे शिकागो की सड़कें दिखाते हुए कहते हैं कि कुछ घंटे पहले यहां तेज तूफान और भारी बारिश हुई थी, लेकिन शहर की रफ्तार पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा.उनके मुताबिक, न बिजली गई, न इंटरनेट बंद हुआ, कहीं पानी नहीं भरा, फुटपाथ नहीं टूटे और ट्रैफिक भी बिना किसी जाम के सामान्य रूप से चलता रहा. वीडियो में यशपाल कहते हैं कि इन लोगों के लिए एडवेंचर का मतलब साइकिल चलाना, रनिंग करना, जिम जाना, आयरनमैन में हिस्सा लेना या स्विमिंग करना है. यहां बारिश और तूफान लोगों के लिए एडवेंचर नहीं बनते.उन्होंने सड़क पर सामान्य रूप से चल रहे ट्रैफिक को दिखाते हुए कहा कि मौसम खराब होने के बावजूद लोगों की दिनचर्या नहीं रुकी.

जापानी फुटबॉल प्रशंसकों के वीडियो ने सिखाया जिम्मेदारी का पाठ

रेड लाइट पर जश्न, ग्रीन होते ही सड़क खाली

फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 के रोमांचक ड्रॉ के बाद टोक्यो की मशहूर शिबुया क्रॉसिंग पर हजारों फुटबॉल प्रशंसक जश्न मनाने पहुंचे. हाथों में झंडे, नारों की गूंज और बारिश के बीच उत्साह का माहौल था. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लोगों का जश्न नहीं, बल्कि उनका अनुशासन चर्चा का विषय बन गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि रेड सिग्नल के दौरान हजारों लोग सड़क पर खड़े होकर अपनी टीम की होसलाअफजाई कर रहे हैं. कोई झंडा लहरा रहा है तो कोई नारे लगा रहा है. लेकिन जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल हरा होता है, पूरा हुजूम बिना किसी हंगामे के कुछ ही सेकंड में सड़क खाली कर देता है. देखते ही देखते गाड़ियां सामान्य रूप से चलने लगती हैं और शिबुया क्रॉसिंग फिर से अपनी रोजमर्रा की रफ्तार में लौट आती है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग जापानी प्रशंसकों की जमकर तारीफ कर रहे हैं.एक यूजर ने लिखा कि इसे ही नागरिक जिम्मेदारी कहते हैं.दूसरे ने कहा कि जश्न मनाइए, लेकिन दूसरों की परेशानी की कीमत पर नहीं. कई लोगों ने लिखा कि नियमों का पालन करना और उत्सव मनाना, दोनों साथ-साथ चल सकते हैं और जापान ने एक बार फिर यह साबित कर दिया. यह जश्न जापान के फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले मुकाबले के बाद मनाया गया. टेक्सास में खेले गए मैच में जापान दो बार पिछड़ने के बावजूद हार नहीं माना.टीम ने 89वें मिनट में गोल कर 2-2 की बराबरी हासिल की और शानदार वापसी करते हुए एक महत्वपूर्ण अंक अपने नाम किया.

'बटवारा 1947' के टीजर ने जगाई 'गदर' की याद सनी देओल की वापसी से बढ़ी दर्शकों की उत्सुकता

बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल एक बार फिर भारत-पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी के साथ बड़े पर्दे पर लौटने जा रहे हैं। उनकी आगामी फिल्म 'बटवारा 1947' का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। फिल्म की पहली झलक देखने के बाद बड़ी संख्या में दर्शकों ने इसे सनी देओल की सुपरहिट फिल्म 'गदर: एक प्रेम कथा' की याद दिलाने वाला बताया है।टीजर में वर्ष 1947 के भारत-विभाजन के दौर की त्रासदी, बिछड़ते परिवारों का दर्द और उस समय की भावनात्मक उथल-पुथल को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। फिल्म में सनी देओल के साथ अभिनेत्री प्रीति जिंटा भी नजर आएंगी, जिनकी वापसी को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।टीजर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर प्रशंसकों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई यूजर्स ने इसे भावनात्मक और प्रभावशाली बताया। एक यूजर ने लिखा कि फिल्म की झलक रोंगटे खड़े कर देने वाली है, जबकि दूसरे ने इसे संभावित ब्लॉकबस्टर करार दिया। कुछ दर्शकों ने मजाकिया अंदाज में सनी देओल की फिल्मों में बार-बार विभाजन की पृष्ठभूमि को लेकर भी टिप्पणी की। वहीं बड़ी संख्या में प्रशंसकों ने इसे 'गदर' की विरासत को आगे बढ़ाने वाली फिल्म बताया।फिल्म की चर्चा के साथ वर्ष 2001 में रिलीज हुई 'गदर: एक प्रेम कथा' का नाम भी लगातार सामने आ रहा है। उस फिल्म में सनी देओल द्वारा निभाया गया तारा सिंह का किरदार आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय पात्रों में गिना जाता है। यही कारण है कि 'बटवारा 1947' को लेकर दर्शकों की अपेक्षाएं काफी बढ़ गई हैं।हालांकि नई फिल्म की कहानी और पात्र पूरी तरह अलग बताए जा रहे हैं, लेकिन विभाजन से जुड़े दर्द, संघर्ष और मानवीय रिश्तों की झलक दर्शकों को पुराने दौर की याद दिला रही है। टीजर में दिखाई गई सिनेमैटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक और भावनात्मक दृश्यों को भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।फिल्म से जुड़ी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन टीजर ने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया है कि 'बटवारा 1947' वर्ष की चर्चित फिल्मों में शामिल हो सकती है। अब दर्शकों की नजर फिल्म की रिलीज और उसके प्रदर्शन पर टिकी हुई है।

सरदार पटेल आवासीय योजना पर स्वामित्व विवाद सिंचाई विभाग के नोटिस से 72 परिवारों में चिंता

लखनऊ की सरदार पटेल आवासीय योजना में भूमि स्वामित्व को लेकर एलडीए और सिंचाई विभाग आमने-सामने आ गए हैं।सिंचाई विभाग ने फ्लैटों पर नोटिस चस्पा कर सात दिनों में क जा हटाने की चेतावनी दी है, जबकि इन आवासों का आवंटन एलडीए द्वारा किया गया था।विवाद के बीच 72 आवंटी परिवार असमंजस में हैं, जिन्हें आशंका है कि सरकारी विभागों के टकराव का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है।

राजधानी लखनऊ की चर्चित सरदार पटेल आवासीय योजना एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला किसी नए आवंटन या विकास कार्य का नहीं, बल्कि जमीन के स्वामित्व को लेकर उठे विवाद का है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) द्वारा विकसित इस आवासीय योजना के फ्लैटों पर सिंचाई विभाग ने नोटिस चस्पा कर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। विभाग ने दावा किया है कि जिन फ्लैटों का निर्माण किया गया है, वह उसकी भूमि पर अवैध रूप से किया गया है। नोटिस में आवंटियों को सात दिनों के भीतर कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है, जिससे फ्लैट धारकों के बीच चिंता और असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसी योजना के फ्लैटों की चाबियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं लाभार्थियों को सौंपी थीं। ऐसे में अब सरकारी विभागों के बीच भूमि स्वामित्व को लेकर शुरू हुआ विवाद चर्चा का विषय बन गया है। जानकारी के अनुसार सिंचाई विभाग ने सरदार पटेल आवासीय योजना के अंतिम छोर पर स्थित फ्लैट पर नोटिस चस्पा किया है। विभाग का कहना है कि संबंधित भूमि उसकी संपत्ति है और उस पर बिना वैधानिक अनुमति के निर्माण किया गया है। नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि सात दिनों के भीतर कब्जा नहीं हटाया गया तो विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं आवंटी की होगी। विभाग ने यह भी उल्लेख किया है कि अवैध कब्जा नहीं हटाने की स्थिति में हर्जा-खर्चा और समन शुल्क भी संबंधित पक्षों से वसूला जाएगा। इस पूरे मामले ने दो सरकारी संस्थाओं को आमने-सामने ला खड़ा किया है। एक ओर LDA का दावा है कि उसने सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए योजना विकसित की है, वहीं दूसरी ओर सिंचाई विभाग भूमि पर अपना अधिकार जता रहा है। भूमि स्वामित्व को लेकर दोनों विभागों के बीच विवाद अब सार्वजनिक रूप से सामने आ गया है। इस विवाद का सीधा असर उन 72 परिवारों पर पड़ सकता है जिन्हें योजना के तहत फ्लैट आवंटित किए गए थे। आवंटियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि दो सरकारी विभाग ही भूमि को लेकर अलग-अलग दावे कर रहे हैं तो उनकी स्थिति क्या होगी। सरदार पटेल आवासीय योजना उस जमीन पर विकसित की गई है जिसे पहले बाहुबली और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी से जुड़ा बताया जाता रहा है। सरकार द्वारा कब्जा मुक्त कराई गई भूमि पर बाद में एलडीए ने इस आवासीय परियोजना को विकसित किया था। सरकार ने इस परियोजना को गरीब और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया था। यही कारण था कि योजना को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। LDA की इस योजना के लिए जब आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी तब लोगों का जबरदस्त रुझान देखने को मिला था। महज 72 फ्लैटों के लिए करीब 8 हजार लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। इससे स्पष्ट था कि राजधानी में सस्ते और सुविधाजनक आवास की मांग कितनी अधिक है।

लखनऊ में 43°C पार करेगा तापमान, हीटवेव का अलर्ट

लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन (19, 20, 21 जून को) हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पार कर जाएगा। बुधवार को अधिकतम तापमान 1.6 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 39.6°C दर्ज हुआ था। न्यूनतम 29.6°C दर्ज हुआ था जो कि सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक बारिश की कोई भी संभावना नहीं जताई है। हालांकि, उसके बाद 23 जून से आंशिक बादल छाए रह सकते हैं लेकिन बारिश नहीं होगी। अगले 3 दिन में तापमान 1-1 डिग्री बढ़ता जाएगा। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी में सतर्क रहने की सलाह दी है। मानसून आने से पहले यूपी में गर्मी के दो अलग मिजाज देखने को मिलेंगे। तय समय पर बारिश नहीं होने से पूर्वांचल के जिलों में तापमान एक बार फिर 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा है। प्रयागराज, वाराणसी और बलिया जैसे जिलों के लिए अगले 3-4 दिनों तक भीषण लू का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, लखनऊ, कानपुर और नोएडा जैसे मध्य व पश्चिमी इलाकों में बारिश के कारण पारा भले ही 38 से 40 डिग्री के बीच रुका समझ में आ रहा है, लेकिन हवा में नमी बढ़ने से चिपचिपी और पसीने वाली गर्मी अपने चरम पर है। इस स्थिति से स्थायी राहत 24 से 25 जून के बीच मानसून की पहली भारी बारिश के बाद ही मिलेगी। तब तक उमस और तपिश का यह मिला-जुला दौर लोगों को झेलना पड़ेगा।

लखनऊ: मोबाइल शॉप में घुसकर हमला, तोड़फोड़ और लूटपाट का आरोप

लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में एक मोबाइल शॉप में घुसकर हमला, तोड़फोड़ और लूटपाट का आरोप लगा है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने नामजद समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना बादलखेड़ा स्थित मोहित मोबाइल शॉप में हुई। सरदार भगत सिंह कॉलेज, शांति नगर कॉलोनी निवासी मनीष वाल्मीकि ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि बुधवार शाम करीब 7:30 बजे दिलीप पाल और सुचित शर्मा अपने 10 से 12 साथियों के साथ उनकी दुकान में जबरन घुस आए। आरोप है कि हमलावरों ने ईंट, पत्थर और हेलमेट से दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। विरोध करने पर दुकान मालिक और कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई, जिससे उन्हें चोटें आईं। पीड़ित मनीष वाल्मीकि के अनुसार, हमलावरों ने दुकान में रखा करीब 50 से 60 मोबाइल फोल्डर क्षतिग्रस्त कर दिए। घटना के बाद दुकान से कुछ मोबाइल फोन भी गायब मिले, जिसके चलते लूटपाट की आशंका जताई गई है। यह पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। घटना के समय आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान और घटना की पुष्टि के लिए जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक सुरेश सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है और जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

24 साल तक जमा की प्लॉट की किस्त, कब्जे वाली जमीन पर बन गया स्कूल

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) में गुरुवार को जनता अदालत में कई तरह की शिकायतें पहुंचीं। किसी ने LDA के अधिकारियों तो किसी ने अपने सगे-संबंधियों पर गंभीर आरोप लगाए। गोमतीनगर विस्तार से पहुंचीं एक महिला ने आरोप लगाया कि LDA के अधिकारी बार-बार शिकायत के बावजूद उनके मोहल्ले से अतिक्रमण नहीं हटवा पा रहे हैं। एक व्यक्ति ने अपनी बहन पर आरोप लगाया कि फर्जी दस्तावेज के जरिये उसने (बहन ने) उनकी जमीन बेच दी है। जानकीपुरम से पहुंचे एक व्यक्ति ने कहा- LDA ने अपनी योजना में उनकी जमीन लेकर उसके एवज में मिला चबूतरा दूसरे के नाम कर दिया। वहीं, एक नेत्रहीन फरियादी ने कहा- मैं 24 साल तक प्लॉट की किस्त जमा करता रहा, वहां पर अब स्कूल बन गया। मेहरबान (सितारा बेगम) ने कहा- 2001 में शारदानगर योजना रजनीखंड लखनऊ में E W S में मुझे प्लॉट आवंटित हुआ था। उसकी किस्त 2024 तक देता रहा। इसे पूरा करने के बाद रजिस्ट्री कराई। यहां (LDA) के अधिकारी बोल रहे हैं कि इस रजिस्ट्री में कब्जा दे दिया गया है, जबकि मुझे कब्जा नहीं मिला और वहां स्कूल बन गया है। कुल 330 वर्गफीट जमीन है। उसमें अब 3 मकान भी बन चुके हैं। 3 लोगों ने कब्जा कर लिया है। अभी मेरे रहने के लिए दूसरी जगह है लेकिन खरीदे प्लॉट पर स्कूल चल रहा है। मैंने 3.50 लाख रुपए में रजिस्ट्री कराई थी। मैं पुलिस के पास गया, यहां वीसी साहब से मिला लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। LDA की जनता अदालत में पहुंचे अमीनाबाद निवासी जसविंदर सिंह ने कहा- माता-पिता के निधन के बाद उनकी बड़ी बहन रमनिक कौर ने 2015 में ट्रांसपोर्टनगर स्थित प्लॉट संख्या एस-165 को उनकी और दूसरी बहन अमृत कौर की सहमति के बिना एक पंजीकृत असाइनमेंट डीड के माध्यम से हस्तांतरित कर दिया। उस समय दोनों भाई-बहन नाबालिग थे और संबंधित संपत्ति एलडीए की लीजहोल्ड संपत्ति थी। उसके बावजूद जमीन बेची गई।

लखनऊ विश्वविद्यालय में धर्मांतरण रोकने के लिए 6 नोडल अधिकारी नियुक्त

लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने धर्मांतरण गतिविधियों की रोकथाम के लिए छह नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की तरफ से जारी निर्देशों के बाद ये कदम उठाए गए है। दावा है कि इससे कैंपस में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा, मानसिक स्वतंत्रता के लिए सुरक्षित माहौल मिल सकेगा। कुलसचिव डॉ.भावना मिश्रा की ओर से जारी आदेश के अनुसार, स्टूडेंट्स को प्रभावित कर, भय दिखाकर, मानसिक दबाव बनाकर अथवा प्रलोभन देकर किए जाने वाले किसी भी प्रकार के अवैध या बलपूर्वक धर्मांतरण को रोकने के लिए कई स्तर पर निवारक उपाय लागू किए जाएंगे। विश्वविद्यालय ने इसके लिए अलग-अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी तय की है। मेंटर-मेंटी सत्रों के माध्यम से छात्रों को जागरूक किया जाएगा। छात्र कल्याण प्रकोष्ठ और संवाद तंत्र को सक्रिय करते हुए विद्यार्थियों की समस्याओं पर लगातार नजर रखी जाएगी। परिसर में काउंसलिंग सेंटरों को मजबूत बनाया जाएगा, जहां छात्र गोपनीय तरीके से अपनी समस्याएं साझा कर सकेंगे।

बेहतर इलाज के नाम पर मरीजों को बहलाने का आरोप, KGMU के बाहर सक्रिय दलाल!

KGMU ट्रॉमा सेंटर के बाहर देर रात निजी एम्बुलेंसों के खड़े होने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में ट्रॉमा सेंटर गेट के बाहर निजी एम्बुलेंस दिखाई दे रही हैं, आरोप है कि इनके जरिए मरीजों को ट्रॉमा सेंटर से प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट कराने का गिरोह सक्रिय है। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि रात होते ही ट्रॉमा सेंटर के बाहर दलाल सक्रिय हो जाते हैं। ये लोग मरीजों और उनके तीमारदारों से संपर्क कर उन्हें बेहतर इलाज का झांसा देकर निजी अस्पतालों में भर्ती कराने का प्रयास करते हैं। इसी मकसद से निजी अस्पतालों से जुड़ीं एम्बुलेंस देर रात तक ट्रॉमा सेंटर के बाहर खड़ी रहती हैं। इस खेल में ट्रॉमा सेंटर के कुछ स्टाफ पर भी गंभीर आरोप हैं। इन पर क्रिटिकल कंडिशन में पहुंचने वाले मरीजों के परिजनों को भ्रमित कर सरकारी अस्पताल में सुविधाएं न मिलने की बात कही जाती है। फिर निजी अस्पतालों में शिफ्ट कराने का दबाव बनाया जाता है। कई मामलों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार भी इस जाल में फंस जाते हैं और उन्हें भारी खर्च उठाना पड़ता है। KGMU प्रशासन का दावा है कि समय-समय पर मरीजों की दलाली रोकने के लिए अभियान चलाने और संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई करने का दावा करता रहा है। बावजूद इसके ट्रॉमा सेंटर के बाहर निजी एम्बुलेंसों की मौजूदगी और दलालों की सक्रियता को लेकर लगातार शिकायतें सामने आती रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अस्पताल परिसर और उसके आसपास निजी एम्बुलेंसों की निगरानी कैसे हो रही है और मरीजों को कथित तौर पर निजी अस्पतालों की ओर ले जाने वाले नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई कब होगी।

मुख्यमंत्री:स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल हुआ उन्नाव विकास अब हजरतगंज तक सीमित नहीं

उन्नाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्टेट कैपिटल रीजन में उन्नाव को भी शामिल किया गया है। अब विकास का कार्य हजरतगंज में नहीं रुकेगा। लखनऊ का विकास अब उन्नाव भी पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली पहली रैपिड ट्रेन की तरह अब लखनऊ से उन्नाव-कानपुर के बीच भी रैपिड ट्रेन चलाई जाने का प्रस्ताव है। इसके माध्यम से हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, लखनऊ को भी जोड़े जाने का प्रस्ताव है। सीएम ने आगे कहा, उत्तर प्रदेश पर प्रभु श्री राम, बांके बिहारी, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद बरस रहा है। बदहाल नहीं हो सकता है। अब यहां पर्व पर उपद्रव नहीं होता है। लोग परिवार के साथ सुरक्षित पर्व मना रहे हैं। पहले सैफई को ही प्रदेश माना जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ जनता को परिवार माना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व विधानसभा के जिन कार्यों का लोकयपन किया है उनमें केकेएम सराय जोगा मार्ग से पहाड़पुर संपर्क मार्ग, हुसैनपुर जमुका पड़री मार्ग से पुरवियन खेड़ा मार्ग, मंगत खेड़ा-कांथा-सोहरामऊ मार्ग पर आरसीसी लघु सेतु का निर्माण, कालूखेड़ा कांथा-मुसन्ना मार्ग पर क्षतिग्रस्त छोटी पुलिया की जगह आरसीसी पुलिया का निर्माण, केकेएम मार्ग पर आरसीसी पुलिया का निर्माण, पुरवा बीघापुर मार्ग पर स्थित नाला पर बॉक्स कल्वर्ट का पुनर्निर्माण, पुरवा-गिलसामऊ-कालूखेड़ा मार्ग पर आरसीसी पुलिया का निर्माण सहित अन्य कार्य शामिल है। इसके साथ ही सदर विधानसभा क्षेत्र के दही चौकी पावर हाउस से अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र दोस्ती नगर बाईपास, मंधना- गंगा बैराज-शुक्लागंज पुरवा-मोहनलालगंज मार्ग चौड़ीकरण, पंडित खेड़ा से आट संपर्क मार्ग सहित अन्य कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली बार उनसे कहा गया कि लखनऊ कानपुर के बीच उन्नाव उपेक्षित महसूस करता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा उन्नाव भी विकसित होगा। अब उन्नाव से दिल्ली और प्रयागराज जाना भी आसान हो गया है। डिफेंस मैन्युफैक्चर कॉरिडोर की स्थापना भी उन्नाव में होगी। उन्नाव को विकसित करने के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण देश आर्थिक मंदी के दौर को भी सफलतापूर्वक निकाल ले गया। समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब कहावत कही जाती थी "देख सपाई बिटिया घबराई"। सपा शासन काल में माफियाओं का राज था। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में विकास कार्य केवल सैफई तक सीमित था। पूरे प्रदेश को दंगा ग्रस्त बना दिया गया था। सपा और कांग्रेस के नेता कभी किसी गरीब के लिए आंसू नहीं बहाते हैं। उनके अंदर गरीबों के प्रति कोई संवेदना नहीं है।

उन्नाव में ट्रांसफार्मर में लगी आग, 200 घरों की बिजली आपूर्ति ठप

उन्नाव शहर के कंचन नगर मोहल्ले में बुधवार देर रात एक ट्रांसफार्मर में आग लगने से विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। इस घटना से आसपास के लगभग 200 घरों की बिजली गुल हो गई, जिससे उपभोक्ताओं को भीषण गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। स्थानीय निवासियों के अनुसार, देर रात बिजली जाने के बाद पता चला कि ट्रांसफार्मर में आग लग गई है। गर्मी और उमस के कारण लंबे समय तक बिजली न आने से लोग काफी परेशान रहे। घरों में पंखे, कूलर और अन्य विद्युत उपकरण बंद हो गए, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को विशेष रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कंचन नगर में खराब हुए ट्रांसफार्मर को बदलने का काम तुरंत शुरू कर दिया गया है। विभागीय कर्मचारी लगातार मौके पर काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द विद्युत आपूर्ति बहाल की जा सके। विद्युत विभाग के एक्सईएन भारत कुमार ने जानकारी दी कि टीमें लगातार क्षेत्रों में पेट्रोलिंग कर रही हैं। जहां भी तकनीकी खराबी की सूचना मिल रही है, वहां कर्मचारियों को भेजकर समस्या का समाधान कराया जा रहा है। उन्होंने पुष्टि की कि कंचन नगर में ट्रांसफार्मर बदलने की प्रक्रिया जारी है और प्रभावित क्षेत्र में बिजली आपूर्ति जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। इसी बीच, गुरुवार को शुक्लागंज क्षेत्र के अलग-अलग इलाकों में भी बिजली उपभोक्ताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ा। कहीं केबल जलने तो कहीं विद्युत तार टूटने के कारण आपूर्ति प्रभावित रही। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि किसी भी विद्युत समस्या की जानकारी तत्काल विभाग को दें, जिससे समय रहते उसका निस्तारण कराया जा सके। गर्मी के मौसम में बढ़ते विद्युत भार के कारण कई जगह तकनीकी समस्याएं सामने आ रही हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जा रहा है।

टीईटी से स्थायी छूट की मांग लेकर महासंघ ने सौंपा ज्ञापन

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश (प्राथमिक संवर्ग) ने केंद्र और प्रदेश सरकार से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के सेवा अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। महासंघ ने उन्नाव कलेक्ट्रेट सभागार में सिटी मजिस्ट्रेट मनोज सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। संगठन ने कहा कि दशकों से सेवा दे रहे शिक्षकों के अनुभव, कार्यकुशलता और योगदान को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। महासंघ के अनुसार, 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त देशभर के शिक्षकों और उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 को टीईटी लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्तियां उस समय के नियमों और निर्धारित पात्रताओं के आधार पर पूरी तरह वैध थीं। महासंघ ने अपने बयान में बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 29 मई 2026 को पुनर्विचार याचिकाओं का निस्तारण करते हुए अपने पूर्व निर्णय को यथावत रखा है। संगठन ने न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए यह भी कहा कि विधि की व्याख्या न्यायपालिका का कार्य है, जबकि जनहित में आवश्यक नीतिगत और विधायी समाधान उपलब्ध कराने का अधिकार संसद और सरकार के पास है। पदाधिकारियों ने तर्क दिया कि बाद में तय किए गए योग्यता मानकों को पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर लागू करना उचित नहीं है। लाखों शिक्षकों और उनके परिवारों के भविष्य को अनिश्चितता में डालने से शिक्षा व्यवस्था की स्थिरता और शिक्षकों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने केंद्र और राज्य सरकार से आग्रह किया है कि ऐसे शिक्षकों को विशेष संरक्षण देने के लिए शीघ्र विधायी, नीतिगत या प्रशासनिक निर्णय लिया जाए। उनकी प्रमुख मांगों में 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त देशभर के शिक्षकों और उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से स्थायी रूप से मुक्त करना शामिल है। साथ ही, उनकी सेवा अवधि, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य सभी वैधानिक सेवा लाभों को सुरक्षित रखा जाए। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि पूर्व नियुक्त शिक्षकों के मामले में न्याय, समानता और विधिक निश्चितता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सरकार को सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए।

उन्नाव हाईवे पर लोडर पलटा, एक युवक की मौत

उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र में लखनऊ-कानपुर हाईवे पर सिंगरोसी मोड़ के पास गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार लोडर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे उसमें सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लोडर तेज गति से हाईवे पर जा रहा था। सिंगरोसी मोड़ के पास अचानक चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और लोडर सड़क पर पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि उसमें सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के दौरान लोडर चालक वाहन से कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि हादसे के बाद वह मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया।पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस उसकी शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। वहीं दुर्घटना के कारणों की जांच करने के साथ-साथ फरार लोडर चालक की तलाश भी कर रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। हादसे के कारण लखनऊ-कानपुर हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। बाद में पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटवाकर यातायात को सुचारू कराया और स्थिति सामान्य कर दी।

उन्नाव में खेत विवाद में महिलाओं-बच्चों समेत 12 लोग घायल

उन्नाव के बीघापुर कोतवाली क्षेत्र के बेहटा भवानी गांव की प्रज्ञा पांडे ने अपने पति, जेठ और नंदोई पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में कोतवाली में तहरीर दी है। प्रज्ञा पांडे ने अपनी तहरीर में बताया कि उनकी शादी 24 नवंबर 2025 को मेथीटीकुर थाना मांखी निवासी शुभम तिवारी से हुई थी। विवाह के बाद से ही उनके पति शुभम तिवारी, जेठ आशुतोष तिवारी, ननद शिखा दीक्षित और नंदोई मनीष दीक्षित द्वारा लगातार एयर कंडीशनर और नकदी की मांग की जा रही थी। दहेज की मांग पूरी न होने पर उपरोक्त लोगों ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आरोप है कि 25 अप्रैल 2026 को मारपीट और धमकी देकर उन्हें घर से निकाल दिया गया। प्रज्ञा ने यह भी बताया कि 7 जून 2026 को बातचीत के बावजूद उनके जेवर आदि वापस नहीं किए गए। कोतवाली प्रभारी अरविंद कुमार ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रज्ञा पांडे की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

उन्नाव: युवक पर धारदार हथियार से हमला, दो आरोपी गिरफ्तार

उन्नाव के सोहरामऊ थाना क्षेत्र के रायपुर खैलामऊ गांव में गुरुवार को एक युवक पर धारदार हथियार से हमला करने के आरोप में पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। गांव निवासी रमाता पत्नी विनोद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मंगलवार शाम करीब आठ बजे उनके घर के बाहर कुछ लोग गाली-गलौज कर रहे थे। जब उनके परिवार ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी। रमाता के अनुसार, इसी दौरान दो हमलावरों ने उनके पुत्र विक्रम पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने उसे तत्काल सीएचसी नवाबगंज में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। थाना प्रभारी अरविंद पांडेय ने जानकारी दी कि पुलिस टीम ने दबिश देकर नामजद आरोपी पंकज कुमार पुत्र हेमराज और हेमराज उर्फ मुखिया पुत्र स्व. चंद्रिका, दोनों निवासी रायपुर खैलामऊ को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की आगे की जांच

सपा में सब ठीक नहीं? दिनेश शर्मा के बयान से यूपी की सियासत में नई हलचल

महिला आरक्षण विधेयक और संगठनात्मक फैसलों को लेकर समाजवादी पार्टी के भीतर असंतोष होने के भाजपा के दावे ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है।राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने आरोप लगाया कि सपा के कई सांसद अपनी राय को पर्याप्त महत्व न मिलने से नाराज हैं।हालांकि सपा की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बयान के बाद पार्टी की आंतरिक स्थिति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर समाजवादी पार्टी के अंदरूनी हालात को लेकर चर्चा तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान दिनेश शर्मा ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के कई सांसद अपनी पार्टी की कार्यप्रणाली और संगठनात्मक व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर कई ऐसे सांसद थे जो महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करना चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छा को महत्व नहीं दिया गया। दिनेश शर्मा के इस बयान के बाद राजनीतिक विश्लेषकों और नेताओं के बीच चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वास्तव में समाजवादी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है या फिर यह भाजपा की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से अभी तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन भाजपा सांसद की टिप्पणी ने सियासी माहौल को जरूर गर्म कर दिया है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने अपने बयान में महिला आरक्षण विधेयक का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि संसद में जब महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा चल रही थी, तब समाजवादी पार्टी के कई सांसद निजी तौर पर इस विधेयक का समर्थन करना चाहते थे। उनका मानना था कि महिलाओं को राजनीति में अधिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। दिनेश शर्मा के अनुसार, कई सांसदों ने पार्टी नेतृत्व से भी इस विधेयक का समर्थन करने की मांग की थी, लेकिन उनकी राय को स्वीकार नहीं किया गया। भाजपा नेता का दावा है कि इससे पार्टी के भीतर असंतोष की भावना पैदा हुई और कई जनप्रतिनिधियों को लगा कि उनकी बातों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है। अपने बयान में दिनेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर भी कई सांसदों और नेताओं में असंतोष है। उनका कहना था कि जब जनप्रतिनिधियों को अपने विचार रखने और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता, तब संगठन के भीतर असहजता पैदा होना स्वाभाविक है। हालांकि, दिनेश शर्मा ने किसी सांसद का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान ने यह संकेत जरूर दिया कि समाजवादी पार्टी के अंदर विभिन्न मुद्दों को लेकर मतभेद मौजूद हो सकते हैं। भाजपा नेता के इस दावे के बाद राजनीतिक हलकों में यह चर्चा शुरू हो गई कि विपक्षी दल के भीतर आंतरिक स्थिति क्या है।

उत्तर प्रदेश के बदांयू में 55 साल के व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई

उत्तर प्रदेश के बदांयू से हत्या की खबर सामने आई है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। बदायूं जिले में गंगा एक्सप्रेस-वे इंटरचेंज के पास 55 साल के व्यक्ति को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या के आरोपियों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने 18 जून को यह जानकारी दी। यह वारदात 17 जून की रात वजीरगंज थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस-वे इंटरचेंज के पास स्थित बनकोटा स्टैंड के करीब हुई। मृतक की पहचान 55 साल के दिलीप यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दिलीप अपनी मोटरसाइकिल का टायर ठीक कराने के लिए सड़क किनारे रुके थे, तभी घात लगाए हमलावर वहां पहुंच गए। PTI के मुताबिक, रात करीब साढ़े आठ बजे बदायूं की ओर से एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक आए और बिना किसी बातचीत के दिलीप यादव पर गोलियां बरसा दीं। फायरिंग के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल दिलीप को इलाज के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हलचल मच गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और जांच शुरू कर दी। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक हृदयेश कठेरिया ने घटनास्थल और मृतक के गांव का दौरा कर पुलिस टीमों को जल्द से जल्द आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के निर्देश दिए। मृतक के बेटे ने पुलिस को बताया कि परिवार की किसी से कोई पुरानी रंजिश या विवाद की जानकारी नहीं है। ऐसे में हत्या के पीछे की वजह अभी साफ नहीं हो सकी है। पुलिस इस मामले में हर पहलू से जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही संदिग्धों की तलाश में दबिश दी जा रही है। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द खुलासे का दावा किया जा रहा है।

सेना की कॉम्बैट यूनिफॉर्म में इस्तेमाल होने वाले कपड़े का बड़ा अवैध भंडारण पकड़ा

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में आर्मी इंटेलिजेंस से मिली सूचना के बाद कैंट थाना इलाके में कार्रवाई की गई। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने नकटिया के मोहनपुर रोड स्थित एक दुकान पर छापा मारकर सेना की कॉम्बैट यूनिफॉर्म में इस्तेमाल होने वाले कपड़े का बड़ा अवैध भंडारण पकड़ा। इस मामले में अरबाज नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से कपड़ा और सेना की यूनिफॉर्म से जुड़ा सामान बरामद किया है।बताया जा रहा है कि आर्मी इंटेलिजेंस की ओर से सूचना दी गई कि नकटिया इलाके में एक दुकान पर सेना की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म में इस्तेमाल होने वाले कपड़े को अवैध तरीके से रखा गया है। साथ ही आशंका जताई गई कि इस कपड़े को कहीं और बेचने की तैयारी की जा रही है। जानकारी मिलते ही मिलिट्री इंटेलिजेंस, कैंट थाना पुलिस और एसओजी की टीम फ़ौरन मौके पर पहुंची और दुकान पर छापा मारा। जांच के समय वहां ऐसा कपड़ा मिला, जो सेना की वर्दी के लिए इस्तेमाल होने वाले पैटर्न से मिलता-जुलता बताया जा रहा है। छापेमारी के वक्त पुलिस ने सात बड़े बंडल बरामद किए, जिनमें प्रत्येक में करीब 200 मीटर कपड़ा था। इसके अलावा पांच अन्य बंडल मिले जिनमें लगभग 100-100 मीटर कपड़ा रखा था। दो प्लास्टिक बैग में करीब 150 मीटर अतिरिक्त कपड़ा भी मिला। केवल कपड़ा ही नहीं, बल्कि सेना से जुड़े अन्य सामान भी मौके से बरामद किए गए। इनमें पी-कैप, कॉम्बैट यूनिफॉर्म से संबंधित सामग्री, जूतों के फीते, कपड़े की टोपी और कई प्लास्टिक पैक में रखे गए काले रंग के वेलको शामिल हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी अरबाज ने बताया कि उसने यह कपड़ा राजस्थान के श्रीगंगानगर स्थित एक फैक्टरी से मंगवाया था। उसका कहना था कि उसने इस कपड़े की खरीद भी कर ली थी और आगे बेचने की तैयारी चल रही थी।

केशव प्रसाद मौर्य, अपना विभाग तो चला नहीं पाते भला सपा के सांसदों को क्या तोड़ेंगे?-शिवपाल यादव

उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों बयानों की जोरदार जंग चल रही है। सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा है। शिवपाल यादव ने राजभर को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि राजभर अगले चुनाव में विधानसभा का मुंह भी नहीं देख पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर भी हमला बोला।ओम प्रकाश राजभर के दावे पर पलटवार करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग सिर्फ झूठ फैलाने का काम करते हैं। वे समय-समय पर ऐसी राजनीतिक साजिशें रचते रहते हैं। राजभर पर तंज कसते हुए शिवपाल यादव ने आगे कहा कि मुझे तो लगता है कि उन्हें सोशल मीडिया पर ट्वीट करने के पैसे मिलते हैं, इसीलिए वे इस तरह की झूठी बातें करते हैं। पूरे यूपी में आज कोई भी ओम प्रकाश राजभर को गंभीरता से नहीं लेता है। वे सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने और चुनाव में सीटें पाने के लिए ऐसी अफवाहें उड़ा रहे हैं। शिवपाल ने साफ किया कि समाजवादी पार्टी का कोई भी सांसद या नेता पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला है। शिवपाल यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दावों को भी हवा-हवाई बताया। सपा के सांसदों को तोड़ने के दावे पर जवाब देते हुए शिवपाल ने कहा कि केशव मौर्य खुद अपनी जीत के लिए सही समीकरण नहीं बना पाते, वो भला सपा के सांसदों को क्या तोड़ेंगे? सपा नेता ने कहा कि केशव मौर्य से अपना खुद का विभाग तो संभलता नहीं है।